भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3801

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक पार्कों के लिए 'प्लग-एंड-प्ले' योजना

3801. श्री गिरिधारी यादवः

श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2024-25 में यथा-घोषित औद्योगिक पार्क परियोजना की 'प्लग एंड प्ले' योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के अनुसार स्थापित किए गए/ स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित बारह औद्योगिक पाकों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सभी बारह औद्योगिक पाकों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या उक्त बारह औद्योगिक पार्कों में से कोई पार्क बिहार में स्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) स्कीम को दिनांक 10.04.2026 को केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य निवेश के लिए पूरी तरह तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास करना है, ताकि निवेशक आसानी से अपने निवेश को क्रियान्वित कर सकें और जिससे देश की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हो सके।

इस स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 33,660 करोड़ है और स्कीम की अवधि 6 वर्ष है।

इस स्कीम के तहत 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। पहले चरण में, एक या अधिक दौर के चयन के जरिए 50 परियोजनाओं को चुना जाना है। पहले चरण के पहले दौर के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 31.07.2026 को बंद कर दिया गया है, और आवेदनों के लिए दूसरा दौर दिनांक 01.08.2026 से खोला गया है।

(ख): केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत निवेश के लिए पूरी तरह तैयार 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के विकास की घोषणा की गई है। इन शहरों को ₹ 28,602 करोड़ की कुल परियोजना लागत से स्थापित किया जा रहा है। स्वीकृत परियोजनाओं की स्थान-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): इन 12 औद्योगिक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): भारत सरकार ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के भाग के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत बिहार राज्य में 1,670 एकड़ भूमि पर गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को 1,339 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ मंजूरी दी है। अब तक, इक्विटी योगदान के रूप में एसपीवी को 135 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शेयरधारक समझौते और राज्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) - बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (बीआईएमसीजीएल) को 6 जनवरी, 2025 को निगमित किया गया था। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी 18 मार्च, 2025 को दी गई थी। एसपीवी इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) संविदाकार द्वारा जुलाई 2025 में नियुक्त नए शहरों के लिए कार्यक्रम प्रबंधक को फरवरी 2026 में नियुक्त किया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3801 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार स्वीकृत औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	**औद्योगिक कॉरिडोर**	**परियोजना का नाम/स्थान**	**क्षेत्र (एकड़)**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**
1	अमृतकर-कोलकाता	खुरपिया, उत्तराखंड	1,002	1,265
2		राजपुरा, पंजाब	1,099	1,367
3		हिसार, हरियाणा	2,988	4,680
4		आगरा, उत्तर प्रदेश	1,058	1,812
5		प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	352	658
6		गया, बिहार	1,670	1,339
7	दिल्ली-मुंबई	दिघी, महाराष्ट्र	6,056	5,469
8		जेपीएमआईए, राजस्थान	1,578	922
9	विजाग-चेन्नई	कोप्पर्थी, आंध्र प्रदेश	2,596	2,137
10	हैदराबाद-बेंगलुरु	ओरवाकल, आंध्र प्रदेश	2,621	2,786
11	हैदराबाद-नागपुर	जहीराबाद, तेलंगाना	3,245	2,361
12	चेन्नई-बेंगलुरु एक्सटेंशन	पलक्कड़, केरल	1,710	3,806
		कुल	**25,975**	**28,602**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3801 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत इन 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है -

क्रम सं.	**परियोजना और कॉरिडोर का नाम**	**स्थिति**
1.	दिघी, महाराष्ट्र - डीएमआईसी	एसएचए और एसएसए का निष्पादन पूर्ण हो गया है। एसपीवी का निगमन पूर्ण हो गया है। प्रयागराज को छोड़कर नए शहरों के कार्यक्रम प्रबंधक (पीएमएनसी) को शामिल किया गया। ईपीसी ने 10 परियोजनाओं को शामिल किया है।
2.	जोधपुर पाली मारवाड़ औद्यगिक क्लस्टर (जेपीएमआईए) - राजस्थान	
3.	राजपुरा, पंजाब - एकेआईसी	
4.	खुरपिया, उत्तराखंड - एकेआईसी	
5.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - एकेआईसी	
6.	गया, बिहार-एकेआईसी	
7.	कोप्पार्थी, आन्ध्र प्रदेश-वीसीआईसी	
8.	ओरवाकल, आंध्र प्रदेश-एचबीआईसी	
9.	ज़हीराबाद, तेलंगाना - एचएनआईसी	
10.	पलक्कड़, केरल - सीबीआईसी एक्सटेंशन।	
11.	हिसार, हरियाणा - एकेआईसी	एसएचए और एसएसए का निष्पादन पूर्ण हो गया है। एसपीवी का निगमन पूर्ण हो गया है। पीएमएनसी को शामिल कर लिया गया है।
12.	आगरा, उत्तर प्रदेश - एकेआईसी	उच्चतम न्यायालय से मंजूरी की आवश्यकता के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि यह भूमि ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) के अंतर्गत आती है।

*****